Question.1 This question contains 15 very short type subquestions. Answer each question in maximum 10 words. All questions are compulsury. Each question carries 03 (Three Marks)

Name- Pradeep Suryavanshi
Test-6 → Paper-2 [1, 2, 3]
Date - 14/02/22 [7987647889]

प्रश्न:

उत्तर :

पू./M = 03 प्राप्तांक

प्रश्न:

उत्तर: (A) (I) ~~संविधान प्रारूप गठन समिति अध्यक्ष अम्बेडकर थे जिनको अंबेडकर प्रारूप स्वतंत्रता विषयों पर विचार विमर्श करना था।~~

पू./M = 03 प्राप्तांक

प्रश्न:

उत्तर: (B) ~~(I) 1973 में पारित (आनंदपुर साहिब पंजाब में)~~
~~(II) पंजाब को स्वायत्त राज्य के रूप में शासित किया~~
~~(III) सुरक्षा, विदेशी संबंध, संचार → केन्द्र को सौंपे~~

पू./M = 03 प्राप्तांक

प्रश्न:

उत्तर: (C) ~~पी.एन भगवती को जनहित याचिका जनक माना जाता है~~

पू./M = 03 प्राप्तांक

प्रश्न:

उत्तर: (D) ~~(1947) के बाद रियासतों के राजाओं को दिया गया विशेष वार्षिक अनुदान, (1971) 26वां संशोधन द्वारा समाप्ति।~~

पू./M = 03 प्राप्तांक

प्रश्न:

उत्तर: (E) (i) निर्देशक तत्व भाग, तथा समाजवादी विचार तत्व
(ii) 42वें संशोधन द्वारा तत्व शामिल
(iii) उद्योगों में श्रमिक भागीदारी प्रोत्साहन पर बल

प्रश्न:

उत्तर: (F) NSCN = नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड
(i) एक अलगाववादी संगठन [नागालिम की स्थापना]

प्रश्न:

उत्तर: (G) (i) 1961 में स्थापित प्रधानमंत्री अध्यक्ष, अन्य सदस्य (मुख्यमंत्री, राजनीतिक दल सदस्य, आदि) उद्देश्य (राष्ट्रीय एकता व अखंडता संबंधित विषयों पर विमर्श

प्रश्न:

उत्तर: (H) (i) नीति आयोग द्वारा स्थापित यह सरकार, NGO, स्वायत्त संगठन के मध्य इन्टरफेस हेतु मंच प्रदान करता है।

प्रश्न:

उत्तर: (I) (i) अटल इनोवेशन मिशन के तहत स्थापित।
(ii) विभिन्न विश्वविद्यालयों में नवाचारों व उद्यमियों को तकनीकी-विशेषज्ञ सहायता प्रदान करती है

उत्तर : (J) (1) शोभ बेकुर भारतीय फोज सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष थे (1926-32) तक

प्रश्न:

उत्तर : (K) (1) यह अधिनियम विदेशी अनुदान को नियन्त्रित करता है जो N.G.O. को प्राप्त होती है 2020 मे संशोधित किया गया है

प्रश्न:

उत्तर : (L) (1) राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक रही

प्रश्न:

उत्तर : (m) यह EVM से जुड़ा तंत्र है जो सत्यापित करता है कि डाला गया मत उसी उम्मीदवार को गया जिसे चयनकर दिया गया था

प्रश्न:

उत्तर : (N) (1) 1987 मे स्थापित → पी. के. थुंगन अध्यक्ष
(II) उद्देश्य → पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सलाह
(III) अनुशंसा → पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए

Question.1 This question contains 15 very short type subquestions. Answer each question in maximum 10 words. All questions are compulsury. Each question carries 03 (Three Marks)

प्रश्न:

पू./M =

उत्तर : (0) उपभोक्ता अधिनियम 1986 धारा 10 द्वारा स्थापित
(1) अध्यक्ष (सेवानिवृत्त न्यायाधीश) 2 अन्य सदस्य (1 महिला)
(14) 1 करोड़ रुपये तक पाये पर क्षेत्राधिकार।

प्रश्न:

पू./M =

उत्तर :

प्रश्न:

पू./M =

उत्तर :

प्रश्न:

पू./M =

उत्तर :

प्रश्न:

पू./M =

उत्तर :

उत्तर :

(A) संविधान अनुच्छेद 129 के तहत SC एक अभिलेखीय न्यायालय है अर्थात उसके द्वारा दिए गए निर्णयों को रिकार्ड व अभिलेखीय रूप से रखा जाता है तथा अन्य न्यायालय, इसी निर्णय के संदर्भ में अपने फैसले सुनाते है। अर्थात सम्पूर्ण भारतीय न्यायालय में उस निर्णय पर प्रश्नचिह्न या अविश्वास नहीं दिखाया जा सकता।

प्रश्न: (2.2)

उत्तर :

(B) NALSA अधिनियम 1987 द्वारा लोकअदालत स्थापित कि जाती है।

शक्तियां → (i) सिविल मामलों में सौहार्दपूर्ण मध्यस्था समाधान करना

(ii) पिड़ित के लिए क्षतिपूर्ति व्यवस्था मुआवजा की मांग करना

(iii) इसे सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त

(iv) स्थायी लोकअदालत द्वारा मामलों पर एक पक्षीय निर्णय भी दिया जा सकता है

उत्तर :

(C) संविधान के प्रस्तावना को संविधान सभा ने अंतिम दिन शामिल किया।

विशेषता → (I) संविधान अपित स्त्रोत स्पष्ट करता है वह भारत के लोग है।

(II) भारत का स्वरूप समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है।

(III) संविधान उद्देश्य समानता, न्याय, बंधुत्व, स्वतंत्रता आदि के शाश्वत भारतवादी तत्व इसे संविधान का भाग मान लिया गया है यह संसद पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है यह संशोधन योग्य है।

प्रश्न: (2.2)

उत्तर :

(D) 44वें संविधान संशोधन द्वारा 19(F) व (31) को निरस्त कर दिया।
अब संपत्ति अधिकार अनुच्छेद (300A) मे शामिल कर दिया गया है।
जिसकी निम्न स्थिति है।

(I) संपत्ति अधिकार अब विधिक अधिकार है

(II) इसके स्थान पर SC/HC/DC जाया जा सकता है

(III) यह कार्यपालिका कार्यवाही से सुरक्षा देता है परन्तु विधिक कार्यवाही से नहीं।

(E) प्रत्येक चुनाव से पूर्व सम्पूर्ण प्रचार रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचरण संहिता जारी कि जाती है

विशेषता → (i) उम्मीदवार व्यवहार को नियंत्रित करना

(ii) भ्रष्ट, दुर्व्यवहार, अनैतिक, आचरण पर रोक

(iii) सामाजिक-धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने से रोकती है

(iv) सभी प्रकार के अनैतिक, गैर कानूनी पर कार्य पर रोक।

(v) उम्मीदवारों व समर्थकों, (दलों) के लिए नैतिक संहिता है परन्तु यह कानूनी बाध्यता पूर्ण नहीं। |

प्रश्न: (2.2)

उत्तर :

(i) अमेरिका पेंटागन द्वारा अनुमोदित रिपोर्ट है जिसके अनुसार चीन सम्पूर्ण दक्षिण पूर्व (दक्षिण चीन सागर, मलक्का खाड़ी, बंगाल खाड़ी) से पूर्वी अफ्रीका तक विभिन्न सामरिक सैन्य बेस बना रहा है ताकि हिन्द-महासागर पर नियंत्रण रख सके तथा प्रभुत्व स्थापित करे।

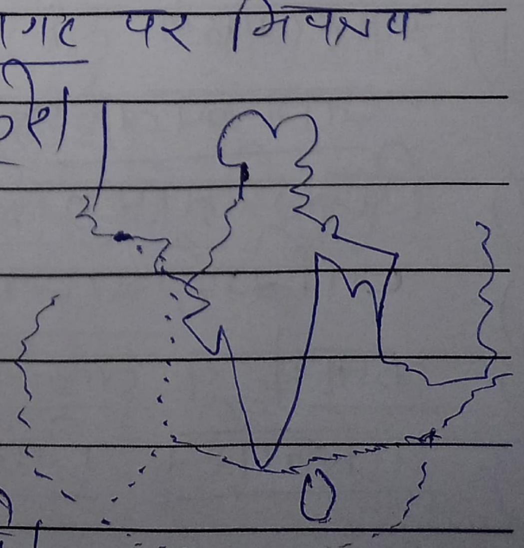

उदा (i) हम्बनटोटा पोर्ट - श्रीलंका

(ii) ग्वादर पोर्ट → पाकिस्तान

(iii) जिबूती → सैन्य बेस कैम्प

आदि स्थापित कर रहा की। स्थापना के प्रयास किए जा सके।

उत्तर :

(ज) इन्द्रा साहनी बनाम भारत संघ 1992 में निम्न निर्णय दिया गया।

(i) आरक्षण की सीमा 50% से अधिक न हो

(ii) पिछड़ा वर्ग आरक्षण में क्रीमीलेयर लागू हो

(iii) SC/ST वर्ग का पदोन्नति आरक्षण में रोक पर नियुक्ति में दिया जाए।

हाल ही में निम्न घटनाओं के कारण चर्चा में

(i) म.प्र. द्वारा 27% OBC आरक्षणवाद।

(ii) राष्ट्रीय स्तर पर 10% EWS आरक्षणवाद

(iv) महाराष्ट्र में मराठा आरक्षणवाद के कारण।

न: (2.2)

उत्तर :

(ग) पंचायतों में (1/3) महिला आरक्षण के बावजूद निम्न चुनौतियाँ विद्यमान।

(i) महिलाओं में अशिक्षा व आत्मनिर्भरता।

(ii) पति का महिला के स्थान भूमिका निभाना

(iii) महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता की कमी।

(iv) पितृसत्तात्मक विचारधारा व अन्य रूढ़िवादिता।

(v) जातिगत भेदभाव व अस्पृश्यता समस्याएं

(vi) कानूनी व तकनीकी प्रशासनिक अकुशलता।

(vii) पारिवारिक जिम्मेदारियां अधिक।

उत्तर :

(I) निम्न तरिको से बढ़ सकता है।

(1) नागरिक अपने मतो को विभिन्न नीतियो पर प्रकट कर सकते है

(11) शोशल मिडिया पर वेब पेज बनाकर जनप्रचार कर समस्या को उजागर करना।

(111) सरकार शोशल मिडिया (survey) लोगो के राय/परामर्श जान सकती है

(iv) सरकारी कार्यक्रमो के क्रियान्वन तथा उसके प्रति जागरूकता में। उदा० स्वच्छभारत अभियान।

प्रश्न: (2.2)

उत्तर :

(J) वे संगठन जिसके जिसके सदस्य सक्रिय रूप से शामिल होकर संगठन हितो की पूर्ती का प्रयास करते हैं। दबाव समूह कहलाते है।

(1) मजदुर संघ → यह श्रमिक दबाव समूह है जो श्रमिक संबंधि मामलो को सरकार के समक्ष उठाता है।

(11) ABVP (अखिलभारतीय विद्यार्थी परिषद) यह विद्यार्थी संबंधि विषयो को सरकार के समक्ष उठाता है।

(ग) संविधान भाग 20 के अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। जो निम्न प्रकार है।

(i) संशोधन प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है।

(ii) संबंधित प्रस्ताव को सदनों द्वारा (अलग-अलग) विशेष बहुमत द्वारा पारित करना होगा (संयुक्त अधिवेशन नहीं)

(iii) यदि संघीय विषयों हो तो आधे राज्यों द्वारा साधारण बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित होना चाहिए।

(iv) तत्पश्चात राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी होगी वो ना ही इंकार कर सकता है न ही पुनः लौटा सकता है।

इससे सम्पूर्ण प्रक्रिया से निम्न कमियां।

Nema Books -9200333367

(i) संशोधन हेतु पृथक संस्था की व्यवस्था नहीं (अमेरिका समान)

(ii) संशोधन की प्रक्रिया मात्र संसद में निहित यहीं से प्रस्ताव आरम्भ होता

(iii) संविधान का महत्वपूर्ण अधिकांश भाग में के संशोधन में राज्यों की भूमिका नहीं है।

(iv) संसद द्वारा संविधान संशोधन पर दी जाने वाली सहमति की समय सीमा तय नहीं।

(v) संविधान संशोधन पर न्यायपालिका द्वारा रोक लगायी जा सकती है न्यायिक समीक्षा माध्यम से।

(vi) संशोधन में संसद द्वारा अन्य कानूनों की तरह सामान्य प्रक्रिया अपनाती है (विशेष बहुमत को छोड़)

(vii) विवाद होने पर संयुक्त अधिवेशन का अभाव।

अत इसी कारण भारतीय संविधान को नम्यता व कठोरता के बीच का संतुलन माना जाता है।

(B) न्यायिक समीक्षा से तात्पर्य संसद, विधान सभा, प्रशासनिक आदेशों के विरुद्ध न्यायालय (SC/HC) द्वारा समीक्षा किया जाना व ही न्यायिक समीक्षा कहा जाता है

आधार – (i) विधायिका की संवैधानिक सीमा का निर्धारण

(ii) नागरिक मौलिक अधिकार सुरक्षा

(iii) प्राधिकरण जिसने विधि/आदेश दिया था उसका अधिकार था है या नहीं की समीक्षा।

(iv) संवैधानिक मूल संरचना की सुरक्षा [केशवानंद भारती वाद (1973)]

विभिन्न संवैधानिक उपबंध जो (SC/HC) शक्ति प्रदान करते हैं।

(i) मौलिक अधिकार (12–35) ~~Article~~

(ii) अनुच्छेद 124 | 226 | 214 |

Nema Books -9200333367

(iii) अनुच्छेद 131/132/133/134

(iv) भारतीय संघात्मक व्यवस्था (246-293) P)

SC ने निम्न मुद्दों पर अपनी न्यायिक ~~की~~ समीक्षा का उपयोग किया

उनमें महत्वपूर्ण है केशवानंद ~~भारतीवा~~ भारतीवाद 1973

इसमें निम्न निर्णय दिए गए

(i) अपने पूर्व निर्णय गोलकनाथवाद को बदला

(ii) संसद संविधान में संशोधन कर सकती है परन्तु संविधान मूल संरचना में नहीं

(iii) अनुच्छेद (31B) को वैध परन्तु (31C) 2) को रद्द कर दिया गया।

अतः न्यायिक समीक्षा की शक्ति के कारण ही भारतीय न्यायपालिका को मौलिक अधिकार व संविधान का संरक्षक कहा गया है।

Nema Books -9200333367

(c) किसी देश के मतदाता किस आधार पर वोट देते है उसका अध्ययन मतदान व्यवहार कहलाता है।
भारतीय संदर्भ मे जाति, धर्म, देश, भाषा, व्यक्तित्व, विचारधारा आदि प्रभावित है वही उत्तराखंड राज्य मे जाति व धर्म भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण बनी हुई है।

(1) जाति → रजनी कोठारी के अनुसार भारतीय राजनिति जातिवादी तथा जाति का राजनीतिकरण इसकी विशेषता है उत्तराखंड मे जातिगत मुख्य पहचान बनी हुई है उ-प्र मे BSP/SP राष्ट्रीय दल आदि का गठन विशेष जातिय समूहो वर्ग के हित की पूर्ति व संगठितकरण हुआ।
यही कारण है प्रत्येक

इस प्रकार U.P में जाति समुदाय के संगठन की कोशिश करता है।

प्रोत्साहक कारक – (i) जातिय पहचान प्रभावित
(ii) अशिक्षा व जागरूकता
(iii) जातिय उम्मीदवार के प्रति विश्वासधारणा
(iv) अन्तर्जातिय वर्गों में विश्वास की कमी
(v) निजि स्वार्थ।

(2) धर्म → सामाजिक-धार्मिक ध्रुवीकरण मतदान व्यवहार का अभूतपूर्व अंग है उत्तरप्रदेश में हिन्दू मुस्लिम वोट तथा (180) अधिक सीटों पर ऐसा प्रभाव जिससे विभिन्न दल अल्पसंख्यक वोट के ध्रुवीकरण हेतु प्रयास करते है। इसी प्रकार धार्मिक पहचान डर। अविश्वास बहुसंख्यक वर्ग में का ध्रुवीकरण करता है।

अतः यह केवल UP में नहीं अपितु सम्पूर्ण भारतीय मतदान व्यवहार की स्थिति की मूल विशेषता है।

(D) मिडिया लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ माना जाता है क्योंकि सरकारी संस्थाओं व शासन के उत्तरदायी स्थापना में मिडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

लोकतंत्र मुख्यतः दो बिन्दुओं पर टीकी है पहली है लोकतांत्रिक संस्थाएं तथा दूसरी है प्रत्यक्ष चुनाव व इन दोनों में मिडिया की भूमिका अति महत्वपूर्ण हो जाती है।

यह निम्न प्रकार इसको पूर्ण करता है

(I) राजनैतिक दुर्व्यवस्था व अहितकारी नीतियों के प्रति जनता को जागरुक कर जिससे ऐसी नीतियों का क्रियान्वन न हो।

(II) यह विभिन्न राजनैतिक विषयों पर सरकार से प्रश्न पूछकर उसे उत्तरदायी बनाती है

(iii) शासन-प्रशासन संबंधि सूचनाओं को सुनिश्चित कर जनता मे प्रसारित करना जिससे शासन मे पारदर्शिता, सुधार को बढ़ावा मिलता है।

(iv) विभिन्न नागरिक समस्याओं को उच्चारित कर सरकार के समक्ष पहुँचाना जिससे उस पर कार्यवाही हो।

(v) सरकारी नीतियों व कार्यक्रमों के प्रति जनता को जागरूक करना।

चुनौतियाँ → (i) 24x7 न्यूज मेकिंग मॉडल।
(ii) कार्पोरेट राजनीतिक हस्तक्षेप।
(iii) विचारधारा से प्रभावित न्यूज चैनल।
(iv) निष्पक्षता का अभाव तथा भ्रामक न होना।

अतः मीडिया को स्वतंत्र, निरपेक्ष, दबाव दमन से सत्य को प्रसारित करना होगा तभी वह चौथा स्तंभ बन सकता है।

Nema Books -9200333367

(E) वे संगठन जिनका प्रशासन सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त होता है तथा वे नागरिक, पर्यावरण आदि हितो मे कार्य करते हो (N.G.O) कहलाते है।

वर्तमान. N.G.O समस्याए

(I) आवश्यकता से अधिक N.G.O सेरब्य संगठन (U.K) अथवा N.G.O उपस्थिति।
(II) नियमो व संरचना मे पारदर्शिता का अभाव
(III) प्राप्त धन का दुरूपयोग (निजि लाभ हेतु)
(IV) मनी लॉन्ड्रिंग व बल्क मनी सबंधि मामलो मे संलिग्न।
(V) सरकारी नीतीयो को अप्रभावी करने का प्रयास तथा कुछ अलगाववादीयो को समर्थन करना आदि।

इस भारत सरकार द्वारा (2014-18) के मध्य 16 हजार N.G.O बंद किए गए।

धनशोधन निवारण हेतु निम्न उपाय उठाए

(i) NGO को (RTI) के अंतर्गत शामिल करें

(ii) पंजीकरण हेतु वित्तीय/संस्थाओं आदि की शर्तों को कठोर बनाए

(iii) संस्थापकों के आधार (ID) को पंजीकरण में शामिल करें

(iv) फंडिंग की सम्पूर्ण व्यवस्था की निगरानी हेतु नियामक तंत्र तथा लेखा-परीक्षा व्यवस्था हो।

(v) मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2005 व FCRA को कठोर किया जाए।

(vi) पंजीकरण से पूर्व उपयुक्त जाँच तथा पंजीकरण का समयानुसार अपडेट्स हो।

(vii) फंडिंग की उच्चतम सीमा निर्धारित करें।

अतः हाल ही में भारत सरकार द्वारा FCRA संशोधन तथा (RTI) को NGO हेतु लागू कर इस दिशा में सराहनीय कदम उठाए है।

Nema Books -9200333367